ग्रामीण परिवेश में बच्चों की स्कूली शिक्षा

ममता देवी*

"Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another. -G.K. CHESTERTON.- अर्थात् शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है।''

'शिक्षा' भाषा बहता नीर जैसी है जो निरंतर गतिमान रहती है एक सदानीरा की तर्ज पर। यह व्यक्ति और समाज के बीच में जितना बटती है उतना ही बढ़ती है। शिक्षा न सिर्फ मनुष्य के अंदर प्रत्येक विषय के बारे में जानने और चीजों को सीखने-समझने की क्षमता विकसित करती है, बल्कि मनुष्य को शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी विकसित करने में उसकी सहायक होती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में गगनचुम्बी सफलताओं को हासिल करता है और कर सकता है। इसलिए हर किसी को शिक्षा के महत्त्व को समझना चाहिए, क्योंकि एक सभ्य और शिक्षित समाज के द्वारा ही देश के आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है और आज के हमारे बच्चे कल का भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। तब जाहिर है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचें और उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैय्या कराने के लिए अथक प्रयास करें।

बच्चा अपनी शुरुआती शिक्षा अपने घर परिवार और समाज में ही ग्रहण करता है। शैक्षिक संस्थाएं तो बाद में उसके जीवन में प्रवेश करती हैं या यों कहें कि वह उन संस्थाओं में प्रवेश करता है। हमारे अपने बड़े-बूढ़े ही छोटे बच्चों को उनकी छोटी उम्र से ही अपनी शिक्षा और जीवन अनुभवों को सिखाते-पढ़ाते रहते हैं। दादी-नानी की कहानियों से ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। इस तरह शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गतिमान रहती है और उसके साथ ही साथ गतिमान होते हैं हमारे सामाजिक संस्कार, नैतिक मानव मूल्य। शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चलती है, लेकिन यह बात उस घर, परिवार और समाज पर लागू होती है जहाँ पर शिक्षा का प्रचार-प्रसार और प्रभाव अत्यधिक है। जो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। हमारे देश की अधिकांश आबादी गाँव में बसती है और गाँव में शिक्षा के प्रति कई बार उदासीनता और अज्ञानता का वातावरण देखने को मिलता है। यही कारण है कि हमारे लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा पर बात करना अतिप्रासंगिक हो जाता है। वर्तमान समय में जहाँ एक ओर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है वहीं दूसरी ओर भारत में पर्याप्त स्कूल और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का अभाव है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर स्कूल नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षा को अर्जित करने के लिए छोटे-छोटे बच्चे एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी तय करते हैं। रोजाना उन्हें धूप, बरसात, ठंडी-गर्मी में दो- तीन मील की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। इसका जीवंत उदाहरण मेरे संज्ञान का एक गाँव (छीट का पुरवा, पोस्ट गौरी, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश-भारत) और मैं खुद हूँ। आज भी मेरे गाँव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हैं और जहाँ वे पढ़ने जाते हैं उस स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्वरूप हम वहाँ के बच्चों के पढ़ने और बोलने से ही अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है? अधिकांश छात्र पहली- दूसरी कक्षा तक की किताब पढ़ने में असमर्थ हैं। इसी तरह के मेरे ही राज्य (उत्तर-प्रदेश) के मेरे ही जिले में अन्य तमाम उदाहरण मिल जायेंगें जहाँ पर न तो स्कूल हैं और न ही स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर है। अन्य स्थानों का भी लगभग यही हाल है। जागरूकता और स्कूलों के अभाव के चलते न जाने कितने मासूम बच्चे अपने जीवन में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और जीविका उपार्जन के लिए कृषि कार्य एवं मजदूरी में लग कर अपने माता-पिता का हाथ बंटाते हैं या फिर बड़े-बड़े नगरों, महानगरों दिल्ली, मुम्बई की ओर पलायन कर जाते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए यह परिस्थिति अभिशाप बनकर उनके सामने आती है। ज्यादातर माँ-बाप अपनी लड़कियों को घर-गाँव से बाहर भेजना उचित नहीं समझते हैं। और कई बार माता-पिता गरीबी की वजह से पुत्र-पुत्रियों में से पुत्र

* भारतीय भाषा केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

को ही शिक्षा हासिल करने के लिए बाहर जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसे में ये लड़कियां अपने जीवन में शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। आज भी हमारा समाज परम्परा और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से बंधा हुआ है जहाँ पर पुरुष को प्रधानता दी जाती है न कि स्त्री को। यह अंतर हमें शिक्षा पर भी दिखाई पड़ता है कि हमारे समाज में बहुत से घर-परिवार ऐसे हैं, जो लड़कियों को शिक्षित करना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं समझते हैं जितना कि लड़कों को। कुछ लोगों का मानना है लड़कियों को शिक्षित करके क्या मिलेगा? आखिर लड़की ही तो है। और लड़की होने से उसके जीवन की ऊंचाईयों का दायरा सीमित करके देखने लगते हैं। ऐसे लोग कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल, इन्दिरा गांधी इत्यादि स्त्रियों के जीवन की सफलताओं को भूल जाते हैं और इस बात को तो बिलकुल भी नहीं समझ पाते कि यदि किसी घर से एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह केवल व्यक्ति ही शिक्षित होता है लेकिन एक स्त्री शिक्षित होती है तो दो परिवार एक साथ शिक्षित होते हैं। ब्रिघम यंग ने कहीं पर कहा है कि- **If you educate man, you educate a man; If you educate a woman, you educate a generation.** (अर्थात् यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित कर रहें हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।) परम्परा, रूढ़िवाद, अज्ञानता, उदासीनता, गरीबी,शिक्षा के प्रति अतत्परता इत्यादि अनेक समस्याएं भारतीय ग्रामीण जीवन में दिखाई देती हैं। जिसके चलते बच्चों को शिक्षा अर्जित करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत अनुभव, टी. वी., अखबार एवं संस्थाओं के सर्वे देखने-पढ़ने के पश्चात् हमें ज्ञात होता है कि हमारे देश के ग्रामीण स्कूलों की क्या दशा है? और शिक्षा की क्या स्थिति है?

ग्रामीण जीवन में स्कूली शिक्षा की स्थिति शोचनीय है। यह बात 'असर (**Annual Status of Education Report & ASER**), 2018 की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि देश में प्राथमिक शिक्षा की दशा और दिशा क्या है ? 'असर' 2018 में ग्रामीण भारत में 3 से 16 वर्ष के बच्चों का स्कूल में नामांकन और 5 से 16 साल के बच्चों के पढ़ने और गणित के सवालों को हल करने की क्षमताओं को परखा गया है। इसमें देश के 596 ज़िलों के कुल 3 लाख 54 हज़ार 944 घरों को शामिल किया गया जिसके ज़रिये 3 से 16 वर्ष के 5 लाख 46 हज़ार 527 बच्चों का सर्वे किया गया।' ये आंकड़े स्कूली शिक्षा के व्यक्ति और समाज के साथ अन्तःक्रिया के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण रुझान देते हैं। रिपोर्ट में स्कूलों में नामांकन और बुनियादी सुविधाओं जैसे पैमानों पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है, लेकिन बच्चों के पढ़ने और गिनने जैसी कुशलताओं में विद्यार्थियों की खस्ता हालत स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया और प्रभाव के बारे तमाम प्रश्न खड़ा करती है।

कक्षा 5 में नामांकित आधे से अधिक छात्र ही कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकें पढ़ पाने में सक्षम हैं। यह आँकड़ा 2016 में 47.9 प्रतिशत था जो 2018 में बढ़कर 50.3 प्रतिशत पर आ गया है। कुछ राज्यों के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के बच्चों ने इस दौरान कुछ सुधार दर्ज़ किया है। ये राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम।

कक्षा 8 : भारत में अनिवार्य स्कूली शिक्षा का अंतिम पड़ाव कक्षा 8 है। इस स्तर पर छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें कम-से-कम बुनियादी कौशल में महारत हासिल हो। किंतु असर (ASER) 2018 के आँकड़ों से यह पता चलता है कि कक्षा 8 के 27 प्रतिशत छात्र कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। यह आँकड़ा 2016 से जस-का-तस बना हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 14 से 16 वर्ष की उम्र के सभी लड़कों में से 50 फीसदी गणितीय भाग (**Devision**) के प्रश्नों को ठीक-ठीक हल कर लेते हैं, जबकि लड़कियों के मामले में सिर्फ 44 फीसदी ही ऐसा कर सकती हैं।

वर्तमान समय में सरकार शिक्षा पर बल दे रही है। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए तमाम तरह की योजनायें चलाई जा रहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार द्वारा गरीब परिवार के बच्चों के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' और मिड-डे मील जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जहाँ पर उन्हें खाने की व्यवस्था की गयी है। अब यह बात अलग है कि बच्चों को खाने के लिए कितना पौष्टिक भोजन मिलता है। यह अपने आप में खुद शोध का विषय है।

सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाये हैं-

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक स्कूली शिक्षा के लिये एक नई एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की है, जो स्कूली शिक्षा की तीन पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान (**SSA**), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (**RMSA**) और केंद्र सरकार की 'शिक्षक शिक्षण अभियान' योजना को एक साथ सम्मिलित करता है। इस योजना का लक्ष्य 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' देना और पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर 12 वीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य सभी के लिये समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है। सीखने के परिणामों को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है जो प्रत्येक विषय और कक्षा में छात्रों की क्षमताओं के लिये एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है।

STARS का पूरा रूप **Strengthening Teaching, Learning and Results for States** है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग' शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की नई परियोजना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है।

इस तरह शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार समय-समय पर प्रयास करती रही है। लेकिन शिक्षा की स्थिति और गुणवत्ता को सुधारने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना होगा। ग्रामीण समाज को शिक्षा प्राप्त करने के प्रति जागरूक होना होगा, हालाँकि कुछ हद तक हैं भी। लेकिन ग्रामीण जीवन में शिक्षा को लेकर काफी विरोधाभास भी देखने को मिलता है। एक तरफ कुछ माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक दिखाई पड़ते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर उदासीन। शहरी समाज जैसी तत्परता अभी भी नहीं दिखाई पड़ती। और यदि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना शहरी स्कूली शिक्षा से की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूली शिक्षा, शहरी स्कूली शिक्षा के समक्ष पानी भरती नजर आएगी। दोनों की व्यवस्थाओं में भी जमीन-आसमान का अंतर है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में श्याम पट्ट भी ठीक से नहीं हैं वहीं शहरी स्कूल के बच्चे लैपटॉप और ईमेल पर भली भांति अध्ययन कार्य करने में सहज हैं। हालाँकि इस कोरोना काल में जब देशबंदी लागू हुई तब जाहिर है कि स्कूल बंदी भी हुई। तब ऐसे में अपनी शिक्षा को निरंतर रूप से गतिशील बनाए रखने के लिए छात्रों ने इन्टरनेट मोबाइल, लैपटॉप और ट्यूशन का सहारा लिया। लेकिन यह सुविधा भी उन्हें ही प्राप्त हो सकी, जो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सबल हैं और जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच आसान रही है। सुदूर ग्रामीण तबका तब भी जैसा का तैसा ही रह गया। लेकिन कुछ माता-पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा एवं भविष्य के प्रति सजगता दिखाई और अस्थाई ट्यूशन-कोचिंग के सहारे उनकी शिक्षा को सुचारु रूप से गतिशील बनाये रखा। ताकि उनके बच्चों के भविष्य पर इस देशबंदी का बहुत गहरा प्रभाव न हो सके। शायद उन्हें अपने बच्चों की योग्यता का अंदाजा है कि वह आने वाले कल में देश और समाज को संवारने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली अध्यापिका कुसुम सिंह का भी 'यही मानना है कि कक्षा में लगभग 50 प्रतिशत बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं बस उन्हें उचित मार्गदर्शन और सही अभ्यास की जरूरत है। यदि उन्हें उचित अवसर और मार्गदर्शन मिलता रहे तो वे अवश्य ही देश और समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं।' इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि ग्रामीण परिवेश से निकले हुए लोगों ने इतिहास में अपना एक मुकाम हासिल किया है चाहे वे डॉ.'राजेन्द्र प्रसाद' हों या फिर 'ओमप्रकाश वाल्मीकि'। इन्होने अपनी कड़ी मेहनत, उचित अवसर एवं उचित मार्गदर्शन के कारण ही अपने जीवन में सफलता हासिल की। ओमप्रकाश वाल्मीकि के शैक्षिक संघर्ष को हम उनकी जीवनी 'जूठन' के माध्यम से देख सकते हैं। आज भी ग्रामीण समाज का बच्चा पढ़ने और स्कूल जाने के प्रति लालायित है। उसकी आँखों में उम्मीद भरे सपने हैं, जिसे वह साकार करना चाहता/चाहती है। उनका यह सपना तभी संभव हो सकता है जब उन्हें उचित शैक्षिक व्यवस्था, उचित अवसर, उचित मार्गदर्शन एवं योग्य अध्यापक प्राप्त हो सकेंगे।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन की शिक्षा को बेहतर करने के लिए शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने पर बल देना होगा और बच्चों के माता-पिता के शैक्षिक विरोधाभास को समाप्त करना होगा तथा इसके साथ ही साथ समाज

की संकुचित मानसिकता और बेटा-बेटी के भेद को भी। शिक्षा के प्रति व्यक्ति, समाज और सरकार सभी को मिलकर सचेत होना पड़ेगा। सरकार को पिछड़े इलाकों में स्कूल एवं अध्यापकों की व्यवस्था और अधिक करनी होगी, जिससे देश के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि शिक्षा पर हर नागरिक का सामान अधिकार है। इसलिए हर किसी को शिक्षा के महत्त्व को समझना चाहिए, क्योंकि एक सभ्य और शिक्षित समाज के द्वारा ही देश के आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि-

कोई भी बच्चा न छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार।
जब होगा शिक्षित हर इंसान, होगा तभी हमारा देश महान्।।

संदर्भ/ सहायक ग्रन्थ-

1. लोक सभा और राज्यसभा टी. वी. डिबेट : देश देशांतर ग्रामीण भारत में शिक्षा एवं चुनौतियां-दृष्टि।

□□□□

विषयावलम्बित छायाचित्र